

आइसीएफआरई में बनेगा डाटा सेंटर

जागरण व्यूरो, देहरादूनः

राज्य में जल्द ही अपना कॉमन डिजिटल डाटा सेंटर शुरू हो जाएगा।

इसके तहत सरकार की ओर से आमजन के लिए चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाओंको ई-डिस्ट्रक्ट के माध्यम से संचालित किया जाएगा। चूंकि इसकी शुरुआत एक अप्रैल से की जानी है, ऐसे में डाटा एकत्र करने के लिए वैकल्पिक डाटा सेंटर बनाया जाना है। इसकेलिए दो स्थानों का चयन किया गया है। इसमें प्रमुख भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई) का डाटा सेंटर है। इसे लेकर शासन स्तर पर लगभग सहमति बन चुकी है। हालांकि शासन अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। केंद्र की ओर से सरकारी योजनाओं को ई-डिस्ट्रक्ट के माध्यम से चलाया जाना है। इसके लिए इन सभी योजनाओं के तहत आने जानकारी का डाटा बैंक बनना है। इन योजनाओं में प्रमुख जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र, खतौनी, जाति प्रमाण-पत्र आदि समेत 23 योजनाएं शामिल हैं। इनका जो भी डाटा तैयार होगा, उसे एक ही स्थान पर जमा किया जाना है। यह सारा डाटा केंद्र की ओर से बनाए जाने वाले आधार कार्ड से लिंक होगा। इस पर जो डाटा एकत्र होगा वह मास्टर डाटा होगा। यानी, किसी व्यक्ति के आधार कार्ड पर उसके संबंध में हर जानकारी एक क्लिक पर ही उपलब्ध हो सकेगी। स्टेट डाटा सेंटर को बनाने के लिए केंद्र की ओर से 6.3 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इनमें से दो करोड़ रुपए राज्य को जारी हो चुके हैं। ऐसे में शासन ने राजकीय निर्माण निगम को डाटा सेंटर के लिए डीपीआर बनाने को कहा है। इस पूरी कवायद में एक वर्ष से अधिक का समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हर राज्य में इस योजना को पहली अप्रैल से शुरू किया जाना है और अभी सूबे का अपना डाटा सेंटर नहीं हैलिहाजा इसके लिए अभी वैकल्पिक डाटा सेंटर बनाने की कसरत जोरों पर है। इसके लिए दो स्थानों का चयन किया गया है। इनमें से एक इन्फारमेशन टेक्नालॉजी डेवलेपमेंट अथोरिटी (आटीडीए) का भवन है, जिसके प्रथम तल में यह बनाया जा सकता है। दूसरा विकल्प आइसीएफआरई का डाटा सेंटर है। यहां पूरी सुविधा होने के साथ ही इस कार्य में दक्ष मानव संसाधन भी मौजूद है। शासन अभी दोनों पहलुओं पर गौर कर रहा है। अपर सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि इन दोनों स्थानों पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। जल्द ही इनमें से किसी एक का चयन कर लिया जाएगा। एक अप्रैल से हर हाल में यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा।